NYCS

RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com

मार्च 2026, नई दिल्ली

पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी 'भारत टैक्सी'

अंदर के पन्नों पर

युवाओं में सहकारिता को लेकर जागरूकता फैला रही सहकार भारती 16

सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत 24

National Yuva Co-operative Society Limited

NYCS

Empowering Financial Independence

Our Services

Loans: Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.

Deposits: Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.

Simplified Process: Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

Our Reach

- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

Why Choose NYCS Ltd.?

- **Trusted Expertise** – Over 20 years in financial services.
- **Nationwide Presence** – A rapidly growing network.
- **Member-Focused** – Tailored financial solutions.
- **Youth Empowerment** – Supporting young entrepreneurs.

Contact Us

209, 2nd Floor, A2B,
Vardhman Janak Market,
Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsindia.com

Together, let's build a brighter financial future!

युवा सहकार

वर्ष : 02, अंक-09, मार्च-2026

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता
दर्शन सोलंकी (विशेष आमंत्रित)
देवेन्द्र सिंह (विशेष आमंत्रित)
रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी (सीईओ)

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं इम्प्रेसन्स प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18-19-20, सेक्टर-59, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी द्वारा मुद्रित।

कार्यकारी संपादक: अभिषेक कुमार
पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

ड्राइवरों की तकदीर बदल रही भारत टैक्सी 04

समावेशी विकास का माध्यम है सहकारिता 05

06 पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी 'भारत टैक्सी'

16 युवाओं में सहकारिता को लेकर जागरूकता फैला रही सहकार भारती

सहकारिता का बढ़ेगा दायरा 18

हर गांव की कोऑपरेटिव होगी मजबूत 21

सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत 24

एनवाईसीएस की नासिक ब्रांच की दूसरी सालगिरह 26

एनवाईसीएस के ईडीपी का सफल आयोजन 27

वन डे क्रिकेट विश्व कप टीम में जोश और अनुभव का होगा संगम! 28

औद्योगिक भ्रमण से एनवाईसीएस प्रशिक्षु हुए लाभान्वित 30

ड्राइवरों की तकदीर बदल रही भारत टैक्सी

हाल ही में कोऑपरेटिव के माध्यम से लॉन्च हुई 'भारत टैक्सी' परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की अभूतपूर्व पहल है। सहकारी क्षेत्र की यह ऐसी अनूठी पहल है जहां ग्राहकों और टैक्सी चालकों दोनों के हितों को ध्यान में रखा गया है। सहकार से समृद्धि के सपने को नया पंख देने वाली इस पहल से अब ओला, उबर, रैपिडो जैसी निजी कंपनियों के भारी कमीशन की मार से परेशान कैब ड्राइवरों को मालिक बनने का मौका मिला है। यह आत्मनिर्भर भारत और सहकार से समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत टैक्सी में अब ड्राइवरों को सम्मान के साथ काम मिल रहा है जिससे उनकी तकदीर बदल रही है। भारत टैक्सी रोजगार, मोबिलिटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है।

कोऑपरेटिव मॉडल पर बनी इस टैक्सी सेवा में ड्राइवर सिर्फ सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि हितधारक भी हैं। 'भारत टैक्सी' का उद्देश्य ड्राइवरों को कंपनी के मुनाफे का मालिक बनाना है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारथियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। आने वाले तीन वर्षों में देश के प्रत्येक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 'भारत टैक्सी' की सेवा उपलब्ध होगी। यह सारथियों को शेयर देकर मालिक बनाने के साथ-साथ उसका बीमा करने और उनहें आसान लोन उपलब्ध कराने वाली पहली टैक्सी सर्विस बनेगी। यह प्लेटफार्म निजी कंपनियों के अधिकतम लाभ अर्जित करने की होड़ के विपरीत पूरी तरह शोषणमुक्त और पारदर्शी बनाने के विजन के साथ स्थापित किया गया है, जहां सारथियों को ज्यादा आमदनी, सम्मान, सुरक्षा और लाभ में हिस्सा इसके चार प्रमुख स्तंभ हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अभी हाल में सारथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सारथी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें उन्होंने भारत टैक्सी के भविष्य के बारे में आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत टैक्सी की कुल कमाई में से बीस प्रतिशत भारत टैक्सी के अकाउंट में सारथियों की पूंजी के रूप में जमा हो जाएगा और अस्सी प्रतिशत पैसा टैक्सी कितने किलोमीटर चली है, उसके अनुसार वापस सारथियों के खाते में जाएगा। इतना ही नहीं, शुरुआती 3 साल भारत टैक्सी के विस्तार में जाएंगे और उसके बाद जितना भी मुनाफा होगा, उसका बीस प्रतिशत भारत टैक्सी में रहेगा और अस्सी प्रतिशत सारथी भाइयों को वापस दे दिया जाएगा।

'भारत टैक्सी' की 'सारथी दीदी' सुविधा महिला सारथियों को स्वावलंबी बनाएगी और महिला यात्रियों व सारथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। चालकों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के साथ ही 'सारथी' शब्द को सम्मान, स्वाभिमान का प्रतीक बनाने के इस कोऑपरेटिव को अमूल, इफको, नेफेड, कृभको, एनडीडीबी, एनसीईएल, नाबार्ड और एनसीडीसी जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त है। भारत टैक्सी की बड़ी खासियत यह है कि यह व्यावसायिक लाभ की आकांक्षा से बनाई गई किसी कंपनी द्वारा चलाई गई ऐप से नियंत्रित नहीं है, जहां कंपनियां ड्राइवर और ग्राहक दोनों की जेब से अधिकतम पैसा निकालने के लिए मनमाने ढंग से कटौती करती रहती हैं। भारत टैक्सी ऐप के जरिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जब कोई यात्री अपनी यात्रा बुक करता है, तो उस पर सारथी यानी ड्राइवर को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसके साथ ही यहां यात्रियों को भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि निजी कंपनियां जहां अधिकतम लाभ अर्जित करने की नीयत से आम तौर पर ट्रैफिक टाइम और देर रात्रि सरचार्ज लगाकर यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलते हैं, जो कभी-कभी सामान्य किराए से दो गुने से भी अधिक होता है। वहीं, भारत टैक्सी के साथ जुड़कर ग्राहक इस ठगी से मुक्ति पा रहे हैं। यह सहकारी मॉडल सेवा की गुणवत्ता के आधार पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत टैक्सी में अब ड्राइवरों को सम्मान के साथ काम मिल रहा है जिससे उनकी तकदीर बदल रही है। भारत टैक्सी रोजगार, मोबिलिटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

समावेशी विकास का माध्यम है सहकारिता

युवा सहकार टीम

'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा एवं नई ऊर्जा प्राप्त हुई है, जिससे 'सहकार से समृद्धि' आज केवल एक नारा नहीं, बल्कि देश के समावेशी विकास का सशक्त मंत्र बन चुका है। केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने इन विचारों को पुणे स्थित वैमनीकॉम में दीक्षांत समारोह के दौरान स्नातकों के बीच साझा किया। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट के 31वें बैच के मेधावियों को उपाधि प्रदान करने के दौरान मोहोल ने कहा कि आज के युवा केवल मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं, बल्कि देश के सहकारी आंदोलन के सशक्त दूत हैं, जो ईमानदारी, पारदर्शिता, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए देश की कृषि-व्यवस्था और सहकारिता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सरकार ने सहकारी विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मोहोल ने कहा कि पैक्स को सशक्त करने, नई बहु-राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना, डेयरी व फिशरीज को बढ़ावा देने तथा देश के पहले त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना जैसे कदम सहकारिता क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से सहकारी संस्थाओं में कार्य क्षमता की कमी, मैनेजमेंट में अनियमितताएं और तकनीकी संसाधनों के सीमित उपयोग जैसी चुनौतियों का समुचित समाधान होगा, जिससे सहकारिता क्षेत्र का दायरा व प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ेगा और नए स्वरोजगार व नवाचार के अवसर भी सृजित होंगे। यह यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता पूरा कर देश के युवाओं में कोऑपरेटिव स्पिरिट विकसित करेगी और उन्हें इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने हर्षपूर्वक कहा कि वैमनीकॉम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से जुड़ने वाला देश का पहला संस्थान है। सहकारिता क्षेत्र के अग्रणी विचारक वैकुंठभाई मेहता जी के नाम पर स्थापित इस संस्था वर्षों से देश को सक्षम, संवेदनशील और कुशल सहकारी प्रबंधक प्रदान किया है। इस संस्थान के माध्यम से अबतक हजारों युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

आज के युवा देश के सहकारी आंदोलन के सशक्त दूत हैं, जो कृषि-व्यवस्था और सहकारिता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं

पैक्स को सशक्त करने, बहु-राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना, डेयरी व फिशरीज को बढ़ावा और सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना से सहकारिता की बढ़ी सामर्थ्य

मोहोल ने कहा कि देश में आज बुनियादी स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) से लेकर शीर्ष सहकारी संगठनों तक सभी स्तरों पर दक्षता, कार्य कुशलता और अनुशासन के लिए योग्य प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आगामी पांच वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में लगभग 17 लाख प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की पहल की गई है, जो सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था को मजबूत करेगी और इसमें देशव्यापी एकरूपता भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि आज देश की लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और हर किसान परिवार से कोई न कोई व्यक्ति सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश में लगभग आठ लाख सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं और इन संस्थाओं में सदस्यों की संख्या 30 करोड़ है।■

भारत टैक्सी के सारथियों के साथ अमित शाह का संवाद

पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी ‘भारत टैक्सी’

- आगामी तीन वर्षों में देश के हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होगी ‘भारत टैक्सी’ सेवा
- ‘सारथी’ को कंपनी के मुनाफे का मालिक बनाना ‘भारत टैक्सी’ का उद्देश्य
- महिला ड्राइवरों को स्वावलंबी बनाएगी ‘सारथी दीदी’ सुविधा

युवा सहकार टीम

भारत टैक्सी की शुरूआत देश के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा कोऑपरेटिव आंदोलन है। सारथी भारत टैक्सी के मालिक हैं और हमारा उद्देश्य टैक्सी के मालिक को धनी बनाना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इन विचारों को नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों के साथ संवाद के दौरान व्यक्त किया। शाह ने जोर देकर कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य किसी निजी कंपनी की तरह बड़ा मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि सारथी भाइयों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी सारथियों की अपनी कंपनी है और इसमें सहकार करना ही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। इसीलिए भारत टैक्सी में कुछ भी छिपा नहीं होगा और सारथियों को हर जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराकर ‘भारत टैक्सी’ दुनिया की सबसे पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी। अमित शाह के अनुसार, भारत टैक्सी का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है क्योंकि सारथी ही इस कोऑपरेटिव का मालिक है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता में सहकारिता क्षेत्र सबसे अहम है और जो मेहनत करेगा, मुनाफा भी उसी को मिलेगा। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्राथमिकता को दोहराते हुए शाह ने कहा कि देश की इस पहली सहकारी क्षेत्र की टैक्सी सर्विस का उद्देश्य ही ड्राइवरों को सीधा फायदा पहुंचाना है।

भारत टैक्सी के मालिक भी हैं सारथी

भारत टैक्सी' के सारथियों से संवाद के दौरान शाह ने उनसे विस्तार से बातचीत की उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उसका समाधान किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के धारा वल्लभ के यह बताने पर कि प्राइवेट कंपनियां कहने को तो हमे पार्टनर बताती है लेकिन वहां वह केवल शब्दभर है, वहां नीतियां अच्छी नहीं हैं, किराए व कमीशन में भी पारदर्शिता नहीं है और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। ऐसे में, भारत टैक्सी सारथी समाज के लिए क्या उक्त समस्याओं को समाधान करेगी? इसके जवाब में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल का जिक्र करते हुए सहकारिता के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताते हुए प्राइवेट और कोऑपरेटिव का अंतर बताया। सहकारिता में होने वाले लाभ का हिस्सा उसके सदस्यों में भी बंटता है और इसी तरह भारत टैक्सी में सारथी बंधुओं की सहभागिता होने से लाभ में भी उनकी हिस्सेदारी होगी। शाह ने कहा कि भारत टैक्सी के शेयर सारथियों के पास हैं और मालिक भी सारथी ही हैं, इसीलिए भारत टैक्सी की नीतियां भी सारथी ही बनाएंगे। शाह ने कहा, 'भारत टैक्सी सारथियों की क्षमता का दोहन करेगी, न कि उनका शोषण करेगी।' उन्होंने कहा कि जो श्रम कर रहा है, उसे ही मुनाफा मिलना चाहिए।

शाह ने कहा कि भारत टैक्सी में मालिक कोई और नहीं, बल्कि सारथी ही हैं। आपको केवल 500 रुपए लगाने हैं। मान लीजिए तीन साल बाद भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपए कमाती है, तो उसमें से 20 प्रतिशत यानी पांच करोड़ रुपए आपकी पूंजी के रूप में संस्था के खाते में जमा होंगे। बाकी 80 प्रतिशत रकम इस आधार पर बांटी जाएगी कि किसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई।' उन्होंने कहा, 'इसका मतलब यह है कि आपको तय किराया तो मिलेगा ही, लेकिन आप मालिक हैं, इसलिए लाभ में भी आपका हिस्सा होगा। यह हिस्सा आपको मिलेगा, पर पहले तीन साल थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा।' शाह ने कहा, 'भारत टैक्सी कुछ भी छिपाकर नहीं रखेगी। हर जानकारी आपको एक सप्ताह पहले सूचना के माध्यम से दे दी जाएगी। आपकी जो न्यूनतम किराया दर तय होगी, लाभ उसी के ऊपर जोड़ा जाएगा। हम कभी भी मूल दर से नीचे नहीं जाएंगे।'

शाह ने 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने के लिए भारत टैक्सी को राष्ट्रव्यापी बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले तीन वर्षों में देश के प्रत्येक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 'भारत टैक्सी'होगी। भारत टैक्सी में सारथियों की प्रति किलोमीटर न्यूनतम व्यवहार्यता की दर की एक बेस लाइन बनाकर काम होगा, जहां ऑटो के मूल्य, पेट्रोल की खपत और न्यूनतम मुनाफे को मिलाकर एक बेस रेट होगा, जिससे नीचे टैक्सी का संचालन नहीं किया जाएगा। शाह ने कहा कि भारत टैक्सी की कुल कमाई में से बीस प्रतिशत भारत टैक्सी के अकाउंट में सारथियों की पूंजी के रूप में जमा हो जाएगा और अस्सी प्रतिशत पैसा सारथियों के खाते में जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरूआती तीन साल भारत टैक्सी के विस्तार

भारत टैक्सी का उद्देश्य किसी निजी कंपनी की तरह केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को मजबूत बनाना है। सभी खाते साफ और पारदर्शी रहेंगे। आपको हर जानकारी समय से पहले दे दी जाएगी। यह व्यवस्था निजी कंपनी की तरह नहीं, बल्कि सहकारिता के सिद्धांतों पर चलेगी। भारत टैक्सी कभी भी आपका शोषण नहीं करेगी।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

- महिला यात्रियों व सारथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी 'भारत टैक्सी' सेवा
- सारथियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करेगी भारत टैक्सी
- 'भारत टैक्सी' में शिकायत विंडो के माध्यम से सारथियों की सभी चिंताओं का होगा समाधान
- सारथियों को शेयर देकर मालिक बनाने के साथ-साथ बीमा और आसान लोन उपलब्ध कराने वाली पहली टैक्सी सर्विस बनेगी
- अन्य टैक्सी कम्पनियों का कमीशन कम करना व यात्रियों को डिस्काउंट देना 'भारत टैक्सी' की शक्ति का ही असर

में जाएंगे और उसके बाद जितना भी मुनाफा होगा, उसका बीस प्रतिशत भारत टैक्सी में रहेगा और अस्सी प्रतिशत सारथी भाइयों को वापस दे दिया जाएगा।

सारथियों की तकलीफों के लिए वेबसाइट पर विंडो खुलेगी

भारत टैक्सी के सारथियों की सभी तकलीफों को दूर करने के लिए आने वाले दिनों में इसकी वेबसाइट bharattaxiapp.com पर एक विंडो खोलने का विजन देते हुए शाह ने कहा कि इस वेबसाइट पर मोबाइल नंबर से लॉग-इन कर सारथी अपनी सारी समस्याएं बता सकेंगे और उनके आधार पर नीतिगत संशोधन करके उसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस प्रकार भारत टैक्सी सारथियों की समस्याओं का निवारण करेगी, उसी प्रकार बाकी टैक्सी कंपनियों को भी यह करना पड़ेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि टैक्सी क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका निवारण एक पद्धति विकसित करने से ही आ सकता है, क्योंकि भारत टैक्सी का लक्ष्य ग्राहक को खुश करने के साथ-साथ सारथी का भी कल्याण करना होना चाहिए। शाह ने कहा कि अभी जो कंपनियां अस्तित्व में हैं, उनका उद्देश्य सारथियों का कल्याण नहीं है। लेकिन, वहीं भारत टैक्सी का उद्देश्य सारथियों के कल्याण के साथ-साथ ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करना भी है। सारथियों में भरोसा जगाते हुए शाह ने कहा कि सारथियों के साथ संवाद और उनकी तकलीफें सुनने का भारत टैक्सी का कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा और सारथियों के साथ ऑनलाइन, फिजिकल और कॉल सेंटर के माध्यम से संवाद जारी होगा।

नई गाडियों के लिए लोन और इंश्योरेंस मिलेगा

एक सारथी के यह पूछने पर क्या हमें नई गाडियों के लिए लोन और इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी और मिलेगी तो कैसे? शाह ने उसकी जिज्ञास को शांत करते हुए बताया कि प्रत्येक सारथी को इफको टोक्यो इंश्योरेंस से जहां बीमा किया जाएगा वहीं नई गाड़ियों की खरीद के लिए उन्हें कोऑपरेटिव बैंक से ऋण की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा, ''कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना होता है। हमारा उद्देश्य भी मालिक को समृद्ध बनाना है। सारथियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं के तौर पर भारत टैक्सी से जुड़ने वाले प्रत्येक सारथी को पांच लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और पांच लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। साथ ही, यहां सारथियों को काम की स्वतंत्रता भी मिल रही है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से भारत टैक्सी एप के साथ-साथ अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर सकते हैं।

सहकारिता का मतलब समझ लें तो सवाल खत्म हो जाएंगे

शाह ने कहा, 'अगर आप सहकारिता की सोच और तरीके को ठीक से समझ लेंगे, तो कोई सवाल उठेंगे ही नहीं। सहकारिता का मतलब है मिलकर काम करना और मिलकर लाभ कमाना। अमूल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गुजरात की 36 लाख माताएं और बहनें इसकी सदस्य हैं। यह एक सहकारी संस्था है, जिसे आम लोगों ने मिलकर खड़ा किया है। इन 36 लाख माताओं और बहनों ने शुरूआत में सिर्फ 50-50 रुपए की पूंजी लगाकर अमूल को बनाया।

धीरे-धीरे और महिलाएं जुड़ती गईं और यह संस्था मजबूत होती चली गई।' उन्होंने आगे कहा, ''आज यही 36 लाख माताओं और बहनों की सहकारी संस्था करीब एक लाख 25 हजार करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। यह दिखाता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो छोटी शुरूआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है। मैं सहकारिता विभाग से आग्रह करूंगा कि वे उन 25 माताओं-बहनों की एक लिस्ट हमारी वेबसाइट पर रखेंगी, जिन्होंने एक साल में एक करोड़ रुपए से ज्यादा का दूध डेयरी को दिया है, यानी उनकी आय एक करोड़ रुपए से ज्यादा है।'

नहीं होगा 'हिडेन चार्ज'

एक सारथी के यह सवाल उठाने पर कि निजी टैक्सी कंपनियों के 'हिडेन चार्जेज' के कारण हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और बहुत कम कमाई हो जाती है। भारत टैक्सी से हमारी कमाई कैसे बढ़ेगी। इसके जवाब में शाह ने कहा कि भारत टैक्सी में कुछ भी हिडेन नहीं है। सब कुछ पारदर्शी है। जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन एक सप्ताह पहले ही सारथी को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न्यूनतम बेस किराया तय किया जाएगा, जिससे सारथी को नुकसान नहीं होगा और किराए के रूप में बेस से अधिक मिलने पर उसका लाभ सारथी को ही मिलेगा।

संवाद के दौरान सारथियों ने अपनी दैनिक चुनौतियों, कमाई, एप पर अनुभव और अपेक्षाओं को शाह से साझा किया और कहा कि भारत टैक्सी में उन्हें पहले से अधिक स्वतंत्रता व आर्थिक लाभ मिला है। शाह ने स्पष्ट कहा कि प्राइवेट कैब कंपनियां सिर्फ अपने बड़े मालिकों की जेब भरती हैं। वहां आपकी मेहनत की कमाई का 30 प्रतिशत हिस्सा वे लोग काट लेते थे और कमाई की कोई गारंटी भी नहीं होती थी। उन्होंने कहा, 'हमारी सोच एकदम सीधी है- जो पसीना बहाए, असली मुनाफा भी उसी को मिले, किसी बड़े सेठ को नहीं। भारत टैक्सी भी अपने मालिकों को ही अमीर बनाना चाहती है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आप ही इसके असली मालिक हैं।' उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत टैक्सी का लक्ष्य ड्राइवरों की आय और गरिमा बढ़ाना है। शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार खुद टैक्सी सेवा नहीं चला रही है बल्कि सहकारी संस्था को बल दे रही है, जिसके मालिक ड्राइवर खुद हैं। उन्होंने सारथियों को को आश्वासन दिया कि प्लेटफॉर्म आगे भी उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा। इसके अलावा समय-समय पर सुधार व नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।■

महिला सारथी बनेंगी स्वावलंबी

सारथी बहन के यह पूछने पर कि सारथियों के मान-सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए भारत टैक्सी में क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, शाह ने जोर देकर कहा कि भारत टैक्सी में सारथी दीदी को स्थान दिया गया है जो महिला सारथियों को स्वावलंबी बनाएगी और इससे महिला यात्रियों व सारथियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत टैक्सी ऐप में सारथी दीदी के नाम से ऐसे प्रावधान किए जाएंगे, जिससे अकेली महिला यात्री स्वाभाविक रूप से सारथी दीदी की टैक्सी को ही प्राथमिकता देगी। शाह ने कहा कि सारथियों को अपने आप को कभी भी ड्राइवर नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन्हें गर्व के साथ स्वयं को सारथी कहना चाहिए। सम्मान के साथ इस भाव को सारथियों के मन में लाना ही भारत टैक्सी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी सुधार की सभी संभावनाओं को तलाशेगी और आगे बढ़ने पर हर समस्या का समाधान भी हो जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि समाज में सारथी को देखने का नजरिया किस प्रकार बदले, यह सारथियों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक अन्य सारथी दीदी के यह पूछने पर कि मैं चाहती हूं कि अगर कोई महिला राइडर भारत टैक्सी पर राइड बुक करे, तो महिला सारथियों को ही इसमें प्राथमिकता मिले। इस पर शाह ने सारथी दीदी को बताया कि भारत टैक्सी में सारथी दीदी का विचार ही इसी सोच से लाया गया है कि महिला सारथियों को महिलाओं की राइड के लिए प्राथमिकता मिले। विशेषकर दो पहिया वाहनों में इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

हमारी सोच एकदम सीधी है- जो पसीना बहाए, असली मुनाफा भी उसी को मिले, किसी बड़े सेठ को नहीं। भारत टैक्सी भी अपने मालिकों को ही अमीर बनाना चाहती है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आप ही इसके असली मालिक हैं।

प्राइवेट कैब सर्विस कंपनियों की मनमानी पर अंकुश

यात्रियों के लिए सुविधा

- ❑ सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन
- ❑ भारत टैक्सी ऐप में एसओएस अलर्ट की सुविधा
- ❑ इमरजेंसी में तुरंत सुरक्षा और सहायता मिलेगी
- ❑ महिला यात्रियों को मिलेगी सारथी दीदी की सेवा
- ❑ ऐप में सारथी दीदी के लिए एक अलग विंडो होगी
- ❑ इससे रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं को सारथी दीदी ही बाइक से पिक करने आएंगी

युवा सहकार टीम

भारत टैक्सी की शुरूआत ने देश के परिवहन क्षेत्र की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। यह न सिर्फ सारथियों के लिए, बल्कि यात्रियों के लिए भी फायदेमंद है। भारत टैक्सी एक सारथी फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जहां सारथी ही इसके सह-मालिक हैं। इसका मकसद सारथियों को शोषण से बचाना, उन्हें कमाई का पूरा हक देना और उचित कीमत पर यात्रियों को पूरी सुरक्षा के साथ गंतव्य तक पहुंचाना है।

भारत टैक्सी के आने से प्राइवेट टैक्सी कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगने लगा है। ये कंपनियां अब तक सारथियों और यात्रियों का शोषण कर अपनी जेब गर्म करती रही हैं। ये न सिर्फ सारथियों एवं टैक्सी मालिकों से भारी कमीशन वसूलती रही हैं, बल्कि पिछले 10 साल से इन्होंने किराया नहीं बढ़ाया है। जबकि इस दौरान पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। इससे सारथियों एवं टैक्सी मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी तरह पीक आवर सर्जिंग चार्ज के नाम पर और बारिश एवं जाम के समय यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलती रहीं है। टिप के नाम पर और अन्य तरीकों से भी ये कंपनियां यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलती हैं। भारत टैक्सी में इस तरह की अवैध गतिविधियां नहीं होती हैं। सारथियों और यात्रियों के बीच भारत टैक्सी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब प्राइवेट टैक्सी कंपनियों ने भी किराया घटाने, यात्रियों को कूपन देना आदि शुरू कर दिया है।

भारत टैक्सी की सेवा अभी देश की राजधानी दिल्ली एवं एनसीआर के शहरों गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद

देश की आठ बड़ी कोऑपरेटिव्स की भागीदारी

अमित शाह ने सारथियों से बातचीत के दौरान कहा कि भारत टैक्सी को देश की आठ बड़ी कोऑपरेटिव्स को मिलाकर खड़ा किया है। जैसे-जैसे सारथियों की संख्या बढ़ती जाएगी और जो भी सारथी इसमें पार्टनर बनना चाहेगा, उसे 500 रुपए के शेयर लेने पर मालिकाना हक मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भारत टैक्सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव होगा, तब इसमें कुछ स्थान सारथियों के लिए भी आरक्षित रखे जाएंगे और जब सारथी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाएंगे तब वे स्वयं अन्य सारथियों के सभी हितों की रक्षा और चिंता करेंगे। शाह ने कहा कि इसके तहत भारत टैक्सी सारथियों की टैक्सी को मॉर्गेज करेगी और भारत टैक्सी ही उन्हें कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से कर्ज दिलाएगी। शाह ने कहा, 'हमारे पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं है कि अकेले इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दें। इसलिए हमने देश की पांच बड़ी सहकारी संस्थाओं को मिलाकर इसकी शुरूआत की है। जैसे-जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी, जो भी सारथी इसमें भागीदार बनना चाहेगा, वह 500 रुपए का अंश लेकर इसका मालिक बन सकेगा। जब भारत टैक्सी के निदेशक मंडल का चुनाव होगा, तब उसमें कुछ स्थान सारथियों के लिए भी तय किए जाएंगे। वे आपके हितों की पूरी चिंता करेंगे।'

के अलावा गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ और द्वारका में उपलब्ध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगले तीन साल में प्रत्येक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारत टैक्सी की सेवा उपलब्ध होगी। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहुत ही कम समय में इससे 3.82 लाख से ज्यादा सारथी और 21.51 लाख से ज्यादा ग्राहक जुड़ चुके हैं। अभी रोजाना करीब 13 हजार राइड की बुकिंग हो रही है और सारथियों को 22 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी है।■

सारथियों को मिल रही ये सुविधाएं

- भारी भरकम कमीशन से मुक्ति, मिल रहा पूरा किराया
- यात्रियों के भुगतान के साथ ही सीधे उनके बैंक अकाउंट में आता है पेमेंट
- ड्राइवर ही इस टैक्सी कंपनी के मालिक, मुनाफे में मिलेगी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी
- 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, बीमा, सस्ते लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर्स की सभी योजनाओं का मिलेगा लाभ
- ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते ही उन्हें और उनके परिवार वालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा

भारत टैक्सी

सहकारिता की अनूठी पहल

दिलीप संघाणी

चेयरमैन, इफको

देश में भारत टैक्सी की शुरूआत सहकारी क्षेत्र में एक ऐसी अनूठी पहल है, जहां ग्राहकों और टैक्सी चालकों, दोनों के हितों को ध्यान में रखा गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय की पहल के तौर पर इस टैक्सी सेवा की शुरूआत की और इसे अमूल जैसी देश की शीर्ष सहकारी संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत और सहकार से समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम है। कोऑपरेटिव मॉडल पर बनी इस टैक्सी सेवा में जहां ड्राइवर सिर्फ सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि हितधारक भी हैं। यह प्लेटफार्म निजी कंपनियों के अधिकतम लाभ अर्जित करने की होड़ के विपरीत पूरी तरह शोषणमुक्त और पारदर्शी बनाने के विजन के साथ स्थापित किया गया है, जहां सारथियों को ज्यादा आमदनी, सम्मान, सुरक्षा और लाभ में हिस्सा इसके चार प्रमुख स्तंभ हैं।

भारत टैक्सी को तीन वर्षों के भीतर देश के सभी छोटे शहरों व ग्रामीण इलाकों तक ले जाने की योजना पर काम हो रहा है, जिससे यह मॉडल कोऑपरेटिव के ड्राइवरों को डिजिटल इकॉनमी में हिस्सेदारी में सक्षम बनाएगा। इस सेवा के तहत अब तक चार लाख से ज्यादा ड्राइवरों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें दिनों-दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। ड्राइवरों से मामूली शुल्क लिया जाएगा। ड्राइवरों को रोजाना भारत टैक्सी ऐप के लिए 30 रुपए का भुगतान करना होगा और वे साप्ताहिक या मासिक आधार पर भी इसका भुगतान कर सकते हैं। इस सेवा के तहत आटो या तिपहिया स्कूटर चलाने वालो को रोजाना सिर्फ 18 रुपए ही देने होंगे।

भारत टैक्सी की बड़ी खासियत यह है कि यह व्यावसायिक लाभ की आकांक्षा से बनाई गई किसी कंपनी द्वारा चलाई गई ऐप से नियंत्रित नहीं है, जहां कंपनियां ड्राइवर

और ग्राहक दोनों की जेब से अधिकतम पैसा निकालने के लिए मनमाने ढंग से कटौती करती रहती हैं। भारत टैक्सी ऐप के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए जब कोई यात्री अपनी यात्रा बुक करता है, तो उस पर सारथी यानी ड्राइवर को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस उपक्रम के मालिक स्वयं ड्राइवर होंगे और अब वे सम्मान के साथ सारथी कहे जाएंगे। भारत टैक्सी का मॉडल जीरो-कमीशन का है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ड्राइवरों को उचित लाभ मिलता रहे। निजी सेवा प्रदाता कंपनियों उबर, ओला और अन्य टैक्सी ऐप में ड्राइवरों को वर्तमान में 10 से 30 प्रतिशत तक का शुल्क देना पड़ता है, जबकि भारत टैक्सी से जुड़ने वाले ड्राइवरों से किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं लिया जा रहा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत टैक्सी में अब ड्राइवर को सम्मान के साथ काम मिल रहा है, जहां सारथी सहकारी टैक्सी सेवा के लिए बनी सहकारी समिति का स्वयं भी सदस्य है। इसके कारण ड्राइवरों में भारत टैक्सी के मालिक होने की भावना मजबूत मिल रही है। यह देश में मोबिलिटी इकोसिस्टम की रीढ़ ड्राइवर का सम्मान है और वे इसके वास्तविक हकदार भी हैं। भारत टैक्सी मॉडल में सारथी अब स्वयं भारत टैक्सी सहकारी संस्था के सदस्य हैं और इसलिए वे निजी कंपनियों के इतर यहां होने वाले लाभों में भी बराबर के हिस्सेदार हैं। यह हिस्सेदारी अमूल मॉडल की तर्ज पर सुनिश्चित की गई है। सर्वविदित है कि अमूल मॉडल में दुग्ध उत्पादक किसानों को अमूल सहकारी संस्था में न केवल दूध का सही मूल्य मिलता है, बल्कि उसके लाभ में भी हिस्सेदारी मिलती है। भारत टैक्सी से जुड़े सारथियों को सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, जिसमें पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बीमा, सस्ते लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर्स के लिए सभी स्कीम जैसे फायदे शामिल हैं।

इसके साथ ही यहां यात्रियों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि निजी कंपनियां जहां अधिकतम लाभ अर्जित करने की नीयत से टैक्सी प्लेटफॉर्म आम तौर पर ट्रैफिक टाइम और देर रात्रि सरचार्ज लगाकर यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलते हैं, जो कभी-कभी तो सामान्य किराए से दो गुने से भी अधिक होता है। वहीं, भारत टैक्सी के साथ जुड़कर ग्राहक इस ठगी से मुक्ति पा रहे हैं और उन्हें ज्यादा मांग के नाम पर अधिक किराए से राहत मिल रही है। यह सहकारी मॉडल सेवा की गुणवत्ता के आधार पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

भारत टैक्सी रोजगार, मोबिलिटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। यह एक जीता-जागता उदाहरण है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देश के हित में काम कर सकता है। जैसे यूपीआई ने भुगतान प्रणाली को बदला, वैसे ही भारत टैक्सी जैसे ओएनडीसी पर आधारित प्लेटफॉर्म सेवा और ई-कॉमर्स को बदलने में सक्षम है। इसतरह, भारत टैक्सी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नहीं है, यह आर्थिक निष्पक्षता के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन है। यह पहल एक मजबूत, आत्मनिर्भर और बराबरी वाले भारत की भावना को दिखाती है।■

भारत टैक्सी की बड़ी खासियत यह है कि यह व्यावसायिक लाभ की आकांक्षा से बनाई गई किसी कंपनी द्वारा चलाई गई ऐप से नियंत्रित नहीं है, जहां कंपनियां ड्राइवर और ग्राहक दोनों की जेब से अधिकतम पैसा निकालने के लिए मनमाने ढंग से कटौती करती रहती हैं। भारत टैक्सी ऐप के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए जब कोई यात्री अपनी यात्रा बुक करता है, तो उस पर सारथी यानी ड्राइवर को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

सहकारिता में सुधारों को मिल रही गति

सहकारी चुनावों में पारदर्शिता और शुचिता सुदृढ़ करने के लिए आयोजित हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी

सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन को मिल रही मजबूती, सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने अब तक 240 चुनाव संपन्न कराए

महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में बढ़ रही समावेशिता

युवा सहकार टीम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि'के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत सरकार सहकारी तंत्र को सशक्त व समर्थ बना रही है। देश में सतत सहकारी विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है, जिससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहकारिताओं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इन विचारों को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान व्यक्त किया। सहकारी चुनावों में पारदर्शिता और शुचिता को सुदृढ़ बनाने को लेकर विचार-विमर्श के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए) के आयोजन में गुर्जर ने कहा कि पहली बार देशभर की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधि एक ही मंच पर एकत्रित हुए हैं और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम सहकारी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।

सहकारी समितियां सहकारी सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जो सहकारी आंदोलन के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार सदस्य समान रूप से योगदान देते हैं और सहकारी संस्थाओं की पूंजी तथा कार्यप्रणाली पर लोकतांत्रिक नियंत्रण रखते हैं, जिससे वे नीतिगत निर्णयों और प्रबंधन प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी कर पाते हैं। सहकारिता राज्यमंत्री शाह ने सहकारी व्यवस्था में जनता का विश्वास बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचा विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने भर्ती और वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रणाली अपनाने पर जोर दिया, जिससे सहकारी संस्थाएं पेशेवर ढंग से संचालित आर्थिक इकाइयों के रूप में विकसित होकर विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान दे सकें।

बहु-राज्यीय सहकारी समितियों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव

सहकारिता राज्य मंत्री गुर्जर ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक अहम फैसले और सुधार किए हैं। मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से किए गए इन महत्वपूर्ण सुधारों का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और लोकतांत्रिक बनाना है। महत्वपूर्ण सुधारों के इस क्रम में स्वतंत्र सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना भी की गई, जिसे 11 मार्च 2024 को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया। इस प्राधिकरण को बहु-राज्यीय सहकारी समितियों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार के तहत बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के निदेशक मंडलों के कार्यकाल की निश्चित समयसीमा तय की गई और उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया, जिनके कारण चुनाव होने तक अनिश्चित समय तक बोर्ड प्रभावी बना रहता था। इस सुधार के जरिए सहकारी संस्थाओं के चुनावों में अनावश्यक विलंब की प्रवृत्ति पर रोक लगी है और उनके प्रशासन में भी अनुशासन आया है।

सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने अब तक करीब 240 चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं और वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी करीब 130 सहकारी संस्थाओं में चुनाव कराए जाने की संभावना है। अब तक कराए गए चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित छह सीटें और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित तेरह सीटें अभी रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए सहकारिता मंत्रालय आवश्यक कदम उठा रहा है। इस प्रकार से सहकारी क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत किया जा रहा है। संशोधित अधिनियम के तहत निदेशक मंडल में महिलाओं के लिए दो तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक सीट आरक्षित किए गए हैं। इससे सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में विविधता और समावेशिता सुनिश्चित हो रही है।

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के जरिए बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों सहित अन्य सहकारी बैंकों के बोर्ड के कार्यकाल को संविधान की व्यवस्था के अनुरूप किया गया है। इसप्रकार से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन को और सुदृढ़ किया गया है। मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत सहकारी बैंकों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे बैंक अपने लेखा परीक्षकों की नियुक्ति केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत पैनल से करें। इससे सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। अब बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों के निदेशक लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकेंगे, जिससे सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में नए और युवा नेतृत्व के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

सहकारिता राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से 5 मार्च 2024 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सहकारी लोकपाल की नियुक्ति की गई है। सहकारी लोकपाल सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा दायर शिकायतों की जांच करता है तथा समितियों के सहकारी सूचना अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। उन्होंने बताया कि अब तक 38 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान सहकारी लोकपाल द्वारा पारित आदेशों के माध्यम से किया जा चुका है।

इस अवसर पर सहकारी चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस अवधि में देशभर में विभिन्न सहकारी संस्थाओं के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराकर महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है।■

सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने अब तक करीब 240 चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं और वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी करीब 130 सहकारी संस्थाओं में चुनाव कराए जाने की संभावना है। अब तक कराए गए चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित छह सीटें और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित तेरह सीटें अभी रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए सहकारिता मंत्रालय आवश्यक कदम उठा रहा है।

युवाओं में सहकारिता को लेकर जा

सहकार भारती देश के प्रमुख सहकारी संगठनों में से एक है। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना, आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देना और समाज को सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मार्ग पर ले जाना है। आने वाले समय में सहकारिता क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। सहकार भारती का भी प्रयास ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सहकारिता से जोड़ने का है। सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री **संजय पाचपोर** से **अभिषेक राजा** और **नुरुल कौसेन** ने तमाम मुद्दों पर लंबी बातचीत की। पेश हैं उसके प्रमुख अंशः

केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई पहल की है, लेकिन जिन राज्यों में सहकारिता पहले से मजबूत नहीं है, वहां इन पहलों का असर अभी उतना दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा?

देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि केंद्र सरकार और विशेष रूप से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन पहलों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में सहकारिता का अनुकूल वातावरण बनाना जरूरी है। आपने सही कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में सहकारिता पहले से ही मजबूत है, लेकिन उत्तर भारत सहित कई राज्यों में सहकारिता उतनी विकसित नहीं है। अगर सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से गांव और प्राथमिक सहकारी संस्थाओं तक पहुंचाया जाए तो वहां भी सहकारिता का विस्तार हो सकता है। मैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के चार जिलों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का दौरा करके आया हूं। वहां तीन प्रमुख चुनौतियां देखने को मिलीं। पहली, प्रशिक्षण का अभाव, दूसरी, सरकारी योजनाओं की जानकारी का नीचे तक न पहुंच पाना और तीसरी सहकारिता के प्रति विश्वास की कमी। इन तीनों क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है।

सहकारिता में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इस पर सहकार भारती का क्या दृष्टिकोण है?

आने वाले समय में युवाओं की भूमिका सहकारिता में बहुत महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, सहकारिता ऐसा क्षेत्र है जिसमें आर्थिक लाभ तुरंत नहीं मिलता। सहकारी संस्थाएं धीरे-धीरे विकसित होती हैं और समय के साथ ही आर्थिक लाभ देती हैं। इसलिए युवाओं को जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम रोजगार हो सकता है। सहकारिता के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। सहकार भारती कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर युवाओं को सहकारिता से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने आणंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की है जिसके माध्यम से युवाओं तक सहकारिता की शिक्षा और विचार पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। हाल ही में एक नई पहल 'भारत टैक्सी' के रूप में सामने आई है, जो सहकारी मॉडल पर आधारित है। दिल्ली-एनसीआर, अहमदाबाद जैसे शहरों में इसकी शुरूआत हो चुकी है। इससे लाखों युवा

जागरूकता फैला रही सहकार भारती

जुड़े हैं। ऐसे नए आयामों के माध्यम से सहकारिता में युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ेगी।

सहकारिता क्षेत्र में भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

सच कहें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार बिल्कुल न हो, लेकिन सहकारिता क्षेत्र को अक्सर ज्यादा बदनाम किया जाता है। सहकार भारती का मूल सिद्धांत है- 'बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार।' सबसे पहले जरूरी है कि संस्कारवान और ईमानदार लोग सहकारिता से जुड़ें। सहकार भारती का प्रयास रहता है कि समाज के अच्छे और जिम्मेदार लोगों को सहकारी संस्थाओं में लाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है प्रशिक्षण। सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। तीसरा कदम है तकनीक और पारदर्शिता। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डिजिटल ऑडिट और अन्य तकनीकी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। इनसे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव होगा।

पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी मनाया गया। इससे भारतीय सहकारिता आंदोलन को क्या लाभ मिला?

इसका लाभ काफी बड़ा रहा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर भारत मंडपम में लगभग 150 देशों की भागीदारी के साथ एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दुनिया के विभिन्न देशों में सहकारिता के अलग-अलग मॉडल काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कमी यह है कि समग्र सहकारिता पर विचार करने वाला कोई वैश्विक संगठन नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों जैसे डेयरी, श्रम, बैंक या क्रेडिट के अपने-अपने संघ हैं, लेकिन समग्र सहकारिता पर काम करने वाला संगठन लगभग नहीं है। इस संदर्भ में सहकार भारती का प्रयास है कि समग्र सहकारिता की सोच को वैश्विक स्तर पर भी बढ़ाया जाए। हमने नेपाल में 'सहकार नेपाल' नाम से एक पहल शुरू की है और भविष्य में इसे अन्य देशों तक भी ले जाने की योजना है।■

आने वाले समय में युवाओं की भूमिका सहकारिता में बहुत महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, सहकारिता ऐसा क्षेत्र है जिसमें आर्थिक लाभ तुरंत नहीं मिलता। सहकारी संस्थाएं धीरे-धीरे विकसित होती हैं और समय के साथ ही आर्थिक लाभ देती हैं। इसलिए युवाओं को जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम रोजगार हो सकता है।

सहकारिता का बढ़ेगा दायरा

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ गांधीनगर में की मंथन बैठक

सहकारिता मंत्री ने राज्यों से अन्न भंडारण, सर्कुलैरिटी और सहकारिता में सहकार पर बल देने का किया आह्वान

कारपेंटर्स, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन जैसे दिहाड़ी मजदूरों के लिए बनेगी नई कोऑपरेटिव, 40 प्रतिशत आबादी को सहकारिता से जोड़ा जाएगा

युवा सहकार टीम

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता को विकसित भारत का आधार बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं क्योंकि वह जानते और मानते हैं कि भारत के हर परिवार, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ सहकारिता ही बन सकती है। 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से इस क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। साथ ही नए-नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करने और मजबूती देने की पहल की जा रही है। इस कड़ी में अभी हाल ही में भारत टैक्सी की शुरूआत की गई है जो सहकारिता के माध्यम से परिवहन क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की क्षमता रखता है। आने वाले दिनों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कारपेंटर्स, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए भी कोऑपरेटिव बनाई जाएगी। इन पहलों के माध्यम से देश की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी को सहकारिता से जोड़ने का सरकार ने लक्ष्य रखा है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से उठाए गए कदमों की समय-समय पर समीक्षा भी होती रहती है। 17 फरवरी को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 'सहकार से समृद्धि' के अंतर्गत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ अमित शाह ने मंथन बैठक की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आने वाले 25 साल तक विश्व के अर्थतंत्र की दिशा निर्धारित करने वाले क्षेत्र में हम आज पायोनियर के रूप में काम कर रहे हैं। इस

मंथन बैठक का आयोजन इसीलिए हो रहा है कि हम 2047 में भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पूर्ण विकसित भारत का अर्थ है कि 140 करोड़ लोग सम्मान के साथ जी सकें, ऐसी व्यवस्था करना। भारत के हर परिवार, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ सहकारिता ही बन सकती है।'

राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से अमित शाह ने आह्वान किया कि कृषि, ग्रामीण विकास और पशुपालन क्षेत्रों को जब तक हम मजबूत नही करते हैं तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। हम सभी को मनोयोग के साथ इस प्रयास को सफल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने वैज्ञानिक तरीके से पिछले चार साल से देश के सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं।

अन्न भंडारण में बढ़े सहकारिता की हिस्सेदारी

मंथन बैठक में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने सहकारिता की स्वीकृति को बढ़ाने वाली बातों पर जोर दिया। इनमें अन्न भंडारण की व्यवस्था पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश की अन्न भंडारण क्षमता को लगभग तीन गुना बढ़ाने की जरूरत है। इसमें से दोगुना सहकारिता क्षेत्र को करनी चाहिए। इसे केवल पैक्स पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ये सभी की जिम्मेवारी है। तहसील की कोऑपरेटिव डेयरियां, राज्य स्तरीय मार्केटिंग फेडरेशन, जिला सहकारी बैंक, जिले के खरीद-बिक्री यूनियन सबको बड़े-बड़े गोदाम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका एक और पहलू है कि सरकारी खरीद का 70 प्रतिशत अनाज पंजाब और हरियाणा में खरीदा जाता है। यहीं से अनाज की खरीदी होगी, यहीं भंडारण होगा और यहीं से वितरित हो जाएगा तो परिवहन की लगत में 30-40 प्रतिशत की बचत हो सकती है।

केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

शुरू की है। इस योजना के तहत 7 करोड़ टन भंडारण की अतिरिक्त क्षमता विकसित की जानी है। इससे न सिर्फ अनाज की बबार्दी रूकेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही भंडारण की व्यवस्था हो जाने से परिवहन लागत में बचत के साथ-साथ अनाज वितरण में भी तेजी आएगी और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अभी देश में अनाज भंडारण की क्षमता 14 करोड़ टन है। अन्न भंडारण योजना के तहत पहले सिर्फ पैक्स को ही गोदाम बनाने का अधिकार दिया गया था, लेकिन गोदाम निर्माण की धीमी रफ्तार को देखते हुए सरकार ने अब सभी इच्छुक सहकारी समितियों को गोदाम बनाने की छूट दे दी है।

बंद चीनी मिलों को शुरू करें राज्य सरकारें

अमित शाह ने राज्यों के सहकारिता मंत्रियों से अपील की कि सभी राज्य बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जिन चीनी मिलों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, वह अलग से उसमें खाद बनाने, गैस बनाने आदि की प्रक्रिया शुरू करें। चीनी मिलों में अलग-अलग प्रकार के 11 उत्पाद बन सके, इसका सफल प्रयोग हो चुका है। मार्च के पहले हफ्ते में इस कार्यरचना को अंतिम रूप दिया जाएगा। जो चीनी मिलें

आने वाले दिनों में देश की अन्न भंडारण क्षमता को लगभग तीन गुना बढ़ाने की जरूरत है। इसमें से दोगुना सहकारिता क्षेत्र को करनी चाहिए। इसे केवल पैक्स पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ये सभी की जिम्मेवारी है। तहसील की कोऑपरेटिव डेयरियां, राज्य स्तरीय मार्केटिंग फेडरेशन, जिला सहकारी बैंक, जिले के खरीद-बिक्री यूनियन सबको बड़े-बड़े गोदाम बनाना चाहिए।

मंथन बैठक में राष्ट्रीय स्तर की तीन नई सहकारी संस्थाओं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएल) में राज्यों की सक्रिय भागीदारी और निर्यात, जैविक खेती और गुणवत्तापूर्ण बीज आपूर्ति के क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

सिर्फ चीनी बना रही है उनमें राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव बाकी का सारा अटैचमेंट कर देगी। इसके लिए राज्यों को अपने यहां लचीली नीति बनानी पड़ेगी। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने सुझाव दिया कि हर राज्य अपने डेयरी और सहकारिता विभाग की टीमों को बनासकांठा डेयरी को देखने के लिए भेजें। बनासकांठा डेयरी ने कई प्रकार के काम किए हैं जिससे सभी राज्यों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा।

सहकारिता में सहकार

'सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सभी सहकारी समितियों को अपना बैंक खाता सहकारी बैंक में ही खोलने का निर्देश दे रखा है। अब इसे और आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में सहकारी बैंक को नोडल एजेंसी बनाने का फैसला किया गया है। शाह ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, वृद्ध पेंशन जैसी योजनाओं का पैसा सहकारी बैंकों के माध्यम से ही दिया जाए। इससे सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

दिहाड़ी मजदूरों के लिए बनेगी कोऑपरेटिव

सहकारिता को नए-नए क्षेत्रों में बढ़ाने की पहल केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ओर से की जा रही है। मंथन बैठक में अमित शाह ने बताया कि आने वाले दिनों में खुदरा मजदूरी करने वाले लोग, जैसे कारपेंटर्स, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, जिनका शोषण होता है उनकी भी कोऑपरेटिव बनाकर उनको सम्मानजनक राशि दिलाई जाएगी। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संभावना तलाश कर आगे बढ़ जा रहा है। इन कदमों से आने वाले दिनों में देश की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी सहकारिता के साथ जुड़ जाएगी। अभी हाल ही में परिवहन क्षेत्र को सहकारिता से जोड़कर भारत टैक्सी की शुरूआत की गई है। शाह के अनुसार, भारत टैक्सी आने वाले कुछ वर्षों में हर एक म्युनिशिपल कॉरपोरेशन तक पहुंच जाएगी। 3 लाख से अधिक चालक इससे जुड़े चुके हैं। इससे चालकों और यात्रियों दोनों को लाभ मिलने वाला है।

265 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने मंथन बैठक में एथेनॉल, एनर्जी, जैविक पोटाश, वेयरहाउस व प्रोटीन पाउडर प्लांट संबंधी 265 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मंथन बैठक में विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से सहकारिता से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर की गई पहलों की प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना का उन्होंने मूल्यांकन किया। इन प्रस्तुतियों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा हुई। इसके साथ-साथ विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत देशभर में आधुनिक गोदामों के नेटवर्क के विस्तार पर बल दिया गया जिससे किसानों को बेहतर भंडारण, मूल्य स्थिरता और बाजार तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके।

मंथन बैठक में राष्ट्रीय स्तर की तीन नई सहकारी संस्थाओं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएल) में राज्यों की सक्रिय भागीदारी और निर्यात, जैविक खेती और गुणवत्तापूर्ण बीज आपूर्ति के क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही राज्यों के सहकारिता कानूनों में समय के अनुसापर सुधार, 97वें संविधान संशोधन के अनुसार मॉडल बायलॉज को अपनाने, सहकारी गन्ना मिलों की आर्थिक व्यवहार्यता तथा लाभ बढ़ाने, डेयरी क्षेत्र में सर्कुलरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी को प्रोत्साहन देने तथा अमूल और एनडीडीबी के सहयोग से नई डेयरी सहकारी समितियों के गठन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।■

हर गांव की कोऑपरेटिव होगी मजबूत

युवा सहकार टीम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरे देश की समृद्धि के लिए प्रयास कर रही है। किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं और सबका विकास सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इन विचारों को ओडिशा में 3770 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण व शुभारंभ के दौरान व्यक्त किया। एक मजबूत और अधिक समृद्ध ओडिशा के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप राज्य के विकास कार्यों को गति देते हुए शाह ने कहा कि राज्य की 173 योजनाओं में से 1230 करोड़ रुपये की लागत वाली 61 योजनाएं पूरी हो गई हैं और 2116 करोड़ रुपये की लागत वाली 112 योजनाओं की शुरूआत की गई है। डेयरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और न्याय संहिता पर ट्रेनिंग से जुड़े ये प्रोजेक्ट राज्य में लोगों की भलाई को बढ़ावा देंगे, युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे, किसानों की समृद्धि को नई रफ्तार देंगे और महिलाओं के सशक्तीकरण के आधार बनेंगे।

शाह ने कहा कि ओडिशा बहुत ज्यादा संभावनाओं वाला राज्य है और इसके पास बड़े तटीय इलाके, बहुत सारे खनिज संपदा और मेहनती आबादी है। सरकार जल्द ही ओडिशा को विकसित राज्यों की सूची में शामिल कराएगी। राज्य में डेयरी की प्रचुर संभावनाएं हैं। आगामी दिनों में यहां डेयरियों के गठन के लिए एक विशेष अभियान के रूप में भारत सरकार और राज्य मिलकर ओडिशा के ग्रामीण जनजीवन को समृद्ध करने के संयुक्त प्रयास के तहत कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से ओडिशा के गरीब किसानों, ग्रामीण

ओडिशा में 3,770 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन

भुवनेश्वर में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) और ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (ओमफेड) के विकास कार्यो का उद्घाटन

पारादीप में इफको के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का लोकार्पण उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बहुत अहम सिद्ध होगा

नई ओडिशा सहकारी नीति-2026 की शुरूआत की गई, जिससे ओडिशा इस तरह की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही, विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें बरम्बा सहकारी चीनी मिल का पुनरुद्धार, कटक में एक आइसक्रीम संयंत्र की स्थापना, एक सहकारी विद्यालय की स्थापना और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की एक शाखा की स्थापना शामिल है।

जनजीवन और विशेषकर माताओं-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। सुभद्रा योजना के तहत राज्य में एक करोड़ माताओं-बहनों को फायदा पहुंचाया गया है। यहां सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से सहकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के तहत इंडियन पोटाश लिमिटेड की बंद चीनी मिल को फिर से शुरू करने के लिए कार्य पूर्ण किया है। सरकार ने बहुत कम समय में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल खरीदने का अपना वादा पूरा किया है।

ओडिशा के हर गांव में होगी सहकारी डेयरी

ओडिशा के विकास के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गुजरात की तरह ही ओडिशा के हर गांव में डेयरी को पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू करेगी। साथ ही, मत्स्य पालन क्षेत्र को भी सहकारी ताकत देकर इसमें बढ़ोत्तरी की जाएगी, जिससे समुद्री भोजन निर्यात में बेहतर अवसर बनेंगे। शाह ने भुवनेश्वर में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) और ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (ओमफेड) के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) और 141 मंडियों का भी उद्घाटन किया और सहकारिता विकास संगोष्ठी के दौरान कहा कि भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय और ओडिशा सरकार मिलकर अमूल की तर्ज पर राज्य में डेयरी विकास को आगे बढ़ाएंगे और हर गांव में कोऑपरेटिव का एक मजबूत आधार बनाने का काम करेंगे।

इस मौके पर नई ओडिशा सहकारी नीति-2026 की शुरूआत की गई, जिससे ओडिशा इस तरह की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही, विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें बरम्बा सहकारी चीनी मिल का पुनरुद्धार, कटक में एक आइसक्रीम संयंत्र की स्थापना और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय में एक विद्यालय की स्थापना और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की एक शाखा की स्थापना शामिल है।

इफको और कृभको उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे

पारादीप में इफको के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र के विशाल प्लांट का लोकार्पण कर अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में इफको और कृभको मिलकर पूरे देश को सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। शाह ने कहा कि इफको ने इस प्लांट को वर्ष 2005 में 2577 करोड़ रुपये में खरीदा था और उस वक्त इसकी क्षमता 7.5 लाख मीट्रिक टन थी, जो आज बढ़कर 22 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। इसमें ब्लेंडेड उर्वरक का उत्पादन लगभग 15 प्रतिशत है और स्वदेशी डीएपी का उत्पादन 40 प्रतिशत है। शाह ने आह्वान किया कि देश में फर्टिलाइजर बनाने वाले हर कारखाने और केमिकल उद्योग में जहां भी सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत हो, उसका उत्पादन इफको की पारादीप यूनिट में होना चाहिए। अब इफको नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और धरती माता के जीर्णोद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम-प्रणाम योजना के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग में कमी लाने का आंदोलन चला रहा है, जिससे हमारी भूमि का संरक्षण होगा। इफको इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव यूनिट बन गई है।

विकास की कमी को पांच वर्षों में पूरा करेंगे

राज्य में विकास के प्रति पिछली सरकारों की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा में दो दशक से भी अधिक समय से विकास रुका हुआ था और राज्य के विकास को ठप कर दिया गया था। उस दौरान जनजातियों के कल्याण के लिए ओडिशा में कोई योजना नहीं बनी, समुद्र तट के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनी और शहरों के विकास के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया। राज्य में सहकारिता और डेयरी क्षेत्र के लिए भी राज्य में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। शाह ने कहा कि आज ओडिशा नए भारत की उम्मीद, ओडिशा की मौलिकता और सभी अवसरों का पता लगाकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार राज्य के साथ मिलकर यहां दो दशकों में विकास की कमी को पांच वर्षों में पूरा करेगी। ■

आज ओडिशा नए भारत की उम्मीद, ओडिशा की मौलिकता और सभी अवसरों का पता लगाकर आगे बढ़ रहा है।

सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत

गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया उद्घाटन

सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपनी शक्ति के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर क्षेत्र में भी अपनी पहचान को बना रहा सशक्त

युवा सहकार टीम

सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के प्रति भारत प्रतिबद्ध है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 10 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि तीन और परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में शीघ्र ही उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हैं। विकसित भारत' के लिए देश के हर कोने में नए तकनीकी केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में मशीन निमार्ता, डिजाइन इंजीनियर, अनुसंधान संस्थान, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और कुशल तकनीशियन के शामिल होने और इन सभी तत्वों के सुचारू समन्वय से ही चिप का उत्पादन होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी उद्देश्य से बजट में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की घोषणा की गई है। उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ भारत में सामग्रियों, घटकों और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। यही सबसे बड़ा अवसर है।

'मेक इन इंडिया' अभियान के पूरी रफ्तार से चलने और पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उत्पादन और निर्यात में हुई कई गुना वृद्धि का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि निवेशकों के लिए घरेलू और वैश्विक बाजार दोनों में ही अवसर मौजूद हैं। साणंद में माइक्रोन संयंत्र एक नए सेमीकंडक्टर

इकोसिस्टम का आधार बनेगा। यह संयंत्र वैश्विक डेटा केंद्रों, एआई अनुप्रयोगों और मोबाइल उपकरणों को शक्ति प्रदान करने के लिए डी-रैम और नैंड समाधानों का उत्पादन करेगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए बनाई गई नीतियां अब जमीनी स्तर पर परिणाम दे रही हैं। गुजरात प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। अनुमोदन, भूमि आवंटन और उपयोगिताओं जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। धोलेरा और साणंद पश्चिमी भारत के सेमीकंडक्टर क्लस्टर के रूप में विकसित हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए आवश्यक इनपुट, जैसे रसायन और पेट्रोकेमिकल्स से संबंधित उद्योगों के साथ-साथ कौशल केंद्र और प्रशिक्षण पहल भी साथ-साथ विकसित किए जा रहे हैं।

मोदी ने कहा कि जहां भारत कभी मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं के लिए जाना जाता था, वहीं अब वह हार्डवेयर क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। साणंद में हम एक नए भविष्य की शुरूआत देख रहे हैं। माइक्रोन के एटीएमपी केंद्र में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए तैयार है। नियमों व प्रक्रियाओं को काफी हद तक सरल बनाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इरादा स्पष्ट होता है और राष्ट्र के तीव्र विकास के प्रति समर्पण होता है, तो नीतियां पारदर्शी हो जाती हैं और निर्णय गति पकड़ते हैं।

वर्तमान सदी एआई क्रांति की सदी है। सेमीकंडक्टर इस बदलाव का सेतु है। यदि 20वीं सदी में तेल नियामक था तो 21वीं सदी में माइक्रोचिप नियामक है। एक छोटी सी चिप औद्योगिक क्रांति को एआई क्रांति से जोड़ने का माध्यम है। इसी सोच के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आक्रामक रूप से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।■

धोलेरा और साणंद पश्चिमी भारत के सेमीकंडक्टर क्लस्टर के रूप में विकसित हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए आवश्यक इनपुट, जैसे रसायन और पेट्रोकेमिकल्स से संबंधित उद्योगों के साथ-साथ कौशल केंद्र और प्रशिक्षण पहल भी साथ-साथ विकसित किए जा रहे हैं।

एनवाईसीएस की नासिक ब्रांच की दूसरी सालगिरह

युवा सहकार टीम

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की नासिक ब्रांच की दूसरी सालगिरह 1 मार्च, 2026 को बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाई गई। खास बात यह है कि दो साल से कम समय में ही इस ब्रांच ने जबरदस्त तरक्की की है। यह तरक्की ब्रांच की शुरूआत से लेकर आज तक सदस्यों और ग्राहक के दिखाए गए भरोसे की वजह से ही मुमकिन हुई है। इस ब्रांच ने भविष्य में ग्राहकों को बेहतर और ज्यादा पारदर्शी सेवा देने का इरादा जताया है।

एनवाईसीएस की नासिक ब्रांच द्वारा दो साल में 3 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ 6 करोड़ रुपये का बिजनेस पूरा करना संगठन की विश्वसनीयता और दक्षता का सबूत है। यह तरक्की सिर्फ सदस्यों, जमाकताओं और ग्राहक के भरोसे की वजह से मुमकिन हुई है। इस ब्रांच ने कोऑपरेटिव क्षेत्र में एक खास जगह बनाई है।

दूसरी सालगिरह के खास मौके पर ब्रांच में श्री सत्यनारायण महापूजन का आयोजन किया गया। इस समारोह में एनवाईसीएस के

दो साल में 3 करोड़ रुपये के एफडी के साथ किया 6 करोड़ का कारोबार

पदाधिकारी, सदस्य, जमाकर्ता, शुभचिंतक और नासिक शहर के जाने-माने लोग शामिल हुए। सालगिरह समारोह बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर नासिक रोड देवलाली व्यापारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री दत्ता गायकवाड़ एवं वर्तमान अध्यक्ष श्री निवृत्ति अरिंगले की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस मौके पर श्री दत्ता गायकवाड़ ने नासिक ब्रांच के काम की तारीफ की और ब्रांच को सिर्फ दो साल में 3 करोड़ रुपये के जमा के साथ 6 करोड़ रुपये का बिजनेस पूरा करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस ब्रांच ने नासिक के लोगों का भरोसा जीतने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। साथ ही, इस तरक्की के लिए एनवाईसीएस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कर्मचारियों की भी तारीफ की।

इस मौके पर शिवसेना नेता श्री अजय बोरस्ते, श्री विनायक पांडे, नगरसेवक श्री प्रशांत दिवे, श्री शिवाजी भोर, श्रीमती रंजना बोराडे, नगरसेविका श्रीमती मंगला आढव, श्री सागर भोजने, श्री योगेश नेसल, श्री गणेश सतभाई, श्री मनोहर कोरडे, श्री योगेश नागरे के साथ-साथ नासिक शहर के भाजपा अध्यक्ष श्री सुनील केदार के साथ-साथ कई गणमान्य लोग, जमाकर्ता, शेयरधारक और शुभचिंतक मौजूद थे।

कार्यक्रम में नासिक ब्रांच सोसायटी के चेयरमैन संजय नरहरि कीर्तने, वाइस चेयरमैन राजेश जगन्नाथ आढव, सेक्रेटरी ज्ञानेश्वर बालासाहेब भोर, डायरेक्टर श्रीमती प्रतिभा विजय सोनवणे के साथ-साथ डायरेक्टर प्रमोद अशोक मुकेर्वार, रवींद्र आनंद शिंदे और नीलेश दिनकर अहिरराव मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान एनवाईसीएस के शुभचिंतकों ने संस्था में जमा करने का वादा किया। यह उम्मीद भी जताई गई कि इस सकारात्मक प्रतिक्रिया से ब्रांच की आगे की तरक्की को और मजबूती मिलेगी।■

एनवाईसीएस के ईडीपी का सफल आयोजन

युवा सहकार टीम

नई दिल्ली के विकासपुरी स्थित एनवाईसीएस-समर्थ स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हाल ही में एक प्रभावशाली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (ईडीपी) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम समर्थ युवा फाउंडेशन एवं नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी द्वारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत संचालित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास से सशक्त बनाना है।

इस प्रशिक्षण सत्र में बड़ी संख्या में कौशल विकास प्रशिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें विशेष रूप से जूनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट एवं दर्जी जॉब रोल से जुड़े प्रतिभागी शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन अनुभवी एवं प्रमाणित मास्टर ट्रेनर द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया, बल्कि व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से उन्हें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से भी अवगत कराया। सत्र के दौरान युवाओं को उद्यमिता के महत्व, कारोबार शुरू करने की बुनियादी समझ तथा बदलते बाजार परिवेश में अवसरों की पहचान करने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रतिभागियों को संचार कौशल, समय प्रबंधन, निर्णय लेने की क्षमता, टीमवर्क और नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रतिभागियों को संचार कौशल, समय प्रबंधन, निर्णय लेने की क्षमता, टीमवर्क और नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इन कौशलों का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि युवाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम बनाना है। प्रशिक्षुओं को यह भी बताया गया कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के माध्यम से वे अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

विशेष रूप से जूनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट प्रशिक्षुओं को ब्यूटी एवं वेलनेस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसरों, ग्राहक प्रबंधन, सेवा गुणवत्ता और व्यक्तिगत ब्रांडिंग के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। वहीं, स्वरोजगार दर्जी जॉब रोल से जुड़े प्रतिभागियों को परिधान निर्माण, डिजाइन की समझ, बाजार की मांग के अनुरूप कार्य करने तथा छोटे स्तर से व्यवसाय प्रारंभ कर उसे विस्तार देने की रणनीतियों से अवगत कराया गया।

ईडीपी सत्र का मुख्य उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। प्रतिभागियों को बाजार की आवश्यकताओं को समझने, तकनीक को अपनाने और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही, उन्हें यह भी समझाया गया कि किस प्रकार वे छोटे स्तर से शुरूआत कर अपने कारोबार को धीरे-धीरे बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं।

इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। कई युवाओं ने अपने विचार साझा किए और भविष्य में स्वयं का स्टार्टअप शुरू करने की इच्छा व्यक्त की। प्रशिक्षण के दौरान आयोजित संवाद, गतिविधियों और चर्चा सत्रों ने वातावरण को जीवंत बना दिया, जिससे प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई।

इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल युवाओं के कौशल विकास में सहायक होते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करते हैं।■

वन डे क्रिकेट विश्व कप टीम में

जोश और अनुभव का होगा संगम!

रोहित शर्मा और विराट कोहली का 2027 विश्व कप टीम में चुना जाना लगभग तय

बेहतर फॉर्म में चल रही रो-को की जोड़ी, उम्र से इस पड़ाव पर भी फिटनेस बरकरार

सत्येन्द्र पाल सिंह

भारतीय क्रिकेट के दो बड़े योद्धा रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। विश्व क्रिकेट में रो-को के नाम से विख्यात यह जोड़ी अब केवल वन डे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रही है। रोहित शर्मा भारत को 2007 और 2024 का आईसीसी टी20 विश्व कप और विराट कोहली 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ शतक के साथ आगाज करते हुए आईसीसी वन डे विश्व कप और 2024 में आईसीसी टी20 विश्व कप जिता चुके हैं।

विराट कोहली को जहां क्रिकेट के दोनों छोटे फॉर्मेट का विश्व कप जिताने का गौरव हासिल है, वहीं अपनी कप्तानी में 2023 के वन डे क्रिकेट विश्व कप में लगातार दस जीत के साथ फाइनल में पहुंच ऑस्ट्रेलिया के हाथों छह विकेट से हार का आज भी मलाल है। 2027 आईसीसी वन डे क्रिकेट विश्व कप तक रोहित शर्मा 40 बरस के और विराट कोहली 39 बरस के हो जाएंगे। तब रो-को की जोड़ी भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के करीब दो दशक पूरा कर लेगी। अब

इस जोड़ी की निगाहें दो बार के चैंपियन भारत को अगले साल नवंबर-दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाम्बे और नामिबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी वन डे विश्व कप जिताने की अनूठी उपलब्धि दिलाने पर लगी है। इस जोड़ी की यही हसरत उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें क्रिकेट खेलना जारी रखने को प्रेरित कर रही है। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजित आगरकर की अगुआई वाली सीनियर राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति आईपीएल 2026 के खत्म होते ही अगले साल होने वाले आईसीसी वन डे क्रिकेट विश्व कप के लिए अपने 20 खिलाड़ियों के कोर ग्रुप को अंतिम रूप दे देगी। मौजूदा फॉर्म और फिटनेस के आधार पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का 2027 के वन डे विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चुना जाना लगभग तय है। यहां सवाल बस यह रहेगा कि सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति भी रो-को जोड़ी पर भरोसा बरकरार रखती है।

2027 के आईसीसी वन डे क्रिकेट विश्व कप से पहले तक करीब डेढ़ बरस में भारत को अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ अपने घर में और इसी साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ उसके घर में तीन-तीन वन डे अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलने जाना है। साथ ही भारत को 2027 में बांग्लादेश में पुरुष वन डे एशिया कप खेलना है। इस लिहाज से भारत को वन डे क्रिकेट विश्व कप से पहले फिलहाल करीब 20 वन डे अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने हैं। हालांकि, बीसीसीआई इसके साथ कई अन्य देशों के खिलाफ भी वन डे अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने की योजना बना रही। यदि यह कार्यान्वित होती है तो फिर भारत वन डे विश्व कप से पहले करीब 26 वन डे अंतरराष्ट्रीय मैच खेल सकता है।

यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे जैसे नौजवान खिलाड़ियों के साथ ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ध्रुव जुरैल जैसे अनुभवी खिलाड़ी बतौर बल्लेबाज टीम इंडिया के

शीर्ष क्रम में जगह पाने के लिए जोरदार ढंग से दस्तक दे रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली का बतौर बल्लेबाज अनुभव, कौशल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में निरंतर बढ़िया करने का जूनून भारतीय टीम में जगह पक्की करता है। इस जोड़ी को लेकर सीनियर राष्ट्रीय क्रिकेट चयनकर्ताओं और अभी हाल ही में अपने मार्गदर्शन में भारत को आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले चीफ कोच गौतम गंभीर को तस्वीर साफ करने की जरूरत है। सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता यदि रोहित और विराट के साथ मिल बैठ कर संवाद में दोनों को यह बता देते हैं कि वे वन डे विश्व कप टीम की योजना का हिस्सा है तो रो-को की जोड़ी और टीम इंडिया दोनों ही सहज होकर आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल यह जोड़ी अपने क्रिकेट कौशल अनुभव, मौजूदा फॉर्म और फिटनेस के आधार पर वन डे विश्व कप में भारतीय टीम की रीढ़ साबित हो सकती है।

यहां एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि वन डे विश्व कप जैसे क्रिकेट के सबसे मंच पर कामयाबी के लिए नए जोश के साथ होश और अनुभव का होना बेहद जरूरी है। मौजूदा आईपीएल में रोहित शर्मा और विराट कोहली एकदम फिट होकर अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए जिस शिद्दत से खेल रहे हैं उससे साफ है कि ये दोनों 2027 के वन डे विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी पूरी मजबूती से पेश करने को बेताब हैं। विराट कोहली ने दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वन डे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज में दो शतक सहित 302 रन बनाए। कुल मिलाकर 2025 में विराट कोहली ने 13 वन डे अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए कुल 651 रन बनाए हैं। बेशक सीनियर चयन समिति पर अनुभवी और नौजवान खिलाड़ियों के बीच संतुलन बैठाने का दबाव है। बावजूद इसके सबसे अहम बात यह है कि विराट बेहतरीन फॉर्म में हैं और रोहित शर्मा अपने चिर परिचित फटाफट क्रिकेट के अंदाज में भारत को वन डे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तेज शुरूआत दे रहे हैं।

वन डे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा 11,577 रन और विराट कोहली 14,797 रन बना चुके हैं। इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने में विराट कोहली (54 शतक), सचिन तेंडुलकर (49 शतक) और रोहित शर्मा (33 शतक) क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। विराट ने वन डे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक सबसे कम 290 पारियों और सचिन तेंडुलकर ने 451 पारियों में बनाए हैं। कोहली का आज भी लक्ष्य का पीछा करने में कोई जवाब नहीं है। लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 29 शतक जड़े हैं और भारत को 24 बार जीत दिलाई।

रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम वन डे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंडुलकर और सौरभ गांगुली (26) के बाद 20 शतकीय भागीदारियां हैं। 2027 वन डे विश्व कप से पहले भारत करीब 20 वन डे अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा। इनमें रो-को की जोड़ी अगर शतकीय भागीदारियां कर सचिन और सौरभ गांगुली की भारत के लिए सबसे ज्यादा शतकीय भागीदारियों के रिकॉर्ड को तोड़ते हैं।■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

औद्योगिक भ्रमण से एनवाईसीएस प्रशिक्षु हुए लाभान्वित

युवा सहकार टीम

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित एनवाईसीएस-समर्थ स्किल डेवलपमेंट सेंटर द्वारा हाल ही में एक प्रभावशाली औद्योगिक भ्रमण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह पहल नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) द्वारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योजना के अंतर्गत संचालित की गई। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पाइप फिटर (ऑयल एंड गैस) और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जॉब रोल से जुड़े प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। उनके लिए यह अनुभव अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक साबित हुआ।

औद्योगिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण को वास्तविक उद्योग जगत से जोड़ना तथा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना था। कक्षा में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक कार्यस्थल पर देखने और समझने का अवसर इस भ्रमण के माध्यम से संभव हो पाया। प्रतिभागियों को गैस पाइपलाइन सिस्टम की संरचना, कार्यप्रणाली, रखरखाव एवं संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से दी गई।

भ्रमण के दौरान विशेषज्ञों ने प्रशिक्षुओं को पाइपलाइन इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया, उपकरणों के उपयोग, तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। इसके साथ ही सुरक्षा प्रोटोकॉल पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षुओं को यह भी समझाया गया कि ऑयल एवं गैस क्षेत्र में कार्य करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित करता

है, बल्कि जीवन की सुरक्षा से भी जुड़ा होता है। इस अनुभव ने प्रतिभागियों को उद्योग के वास्तविक कार्य वातावरण से परिचित कराया। उन्होंने देखा कि किस प्रकार टीमवर्क, समय प्रबंधन एवं तकनीकी दक्षता मिलकर किसी भी परियोजना को सफल बनाते हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई तथा उन्होंने अपने करियर के प्रति अधिक स्पष्टता प्राप्त की।

औद्योगिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण को वास्तविक उद्योग जगत से जोड़ना तथा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना था।

औद्योगिक भ्रमण के दौरान प्रशिक्षुओं को उद्योग विशेषज्ञों से संवाद करने का अवसर भी प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने अपने प्रश्नों के उत्तर पाए और करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कीं। यह संवादात्मक अनुभव उनके लिए अत्यंत उपयोगी रहा क्योंकि इससे उन्हें उद्योग की अपेक्षाओं एवं वर्तमान रुझानों को समझने में सहायता मिली। इस प्रकार के औद्योगिक भ्रमण न केवल प्रशिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाते हैं, बल्कि प्रशिक्षुओं में व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं और उनके कौशल को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में सहायक होते हैं।

एनवाईसीएस-समर्थ द्वारा आयोजित यह औद्योगिक भ्रमण युवाओं के लिए सीखने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। इसने न केवल उनके तकनीकी ज्ञान को सुदृढ़ किया, बल्कि उन्हें एक सफल पेशेवर बनने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और दृष्टिकोण भी प्रदान किया।■

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

SERVING **FARMERS** **TO GROW** BOUNTIFUL

KRIBHCO world's premier fertilizer producing cooperative has been consistently making sustained efforts towards promoting modern agriculture and cooperatives in the country. It helps farmers maximize their returns through specialised agricultural inputs and other diversified businesses.

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD

Registered Office: A-60, Kailash Colony, New Delhi-110048 | **Phone: 011-29243412**
Corporate Office: KRIBCHO BHAWAN, A 8-10, Sector-1, Noida-201301, Distt: Gautam Budh Nagar (UP) | **Phones:** 0120-2534631/32/36
Website: www.kribhco.net | **KRIBCHO Kisan Helpline:** 0120-2535628 | **E-mail:** krishipramarsh@kribhco.net

OUR PRODUCTS

Neem Coated Urea | DAP | MOP | NPK | NPS | MAP | Liquid Bio Fertilizers | Certified Seeds | Hybrid Seeds
City Compost | Zinc Sulphate | Natural Potash | Sivarika | Rhizosuper

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF EDUCATION
Government of India
सत्यमेव जयते

nbt.india
एकः सूते सकलम्

उत्तराखण्ड राज्य

नगर निगम देहरादून
Uttarakhand India

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
द्वारा आयोजित

सभी पुस्तकों पर 10% की छूट

प्रवेश निःशुल्क

DOON
BOOK FESTIVAL

4-12 अप्रैल 2026

प्रात: 10:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे

परेड ग्राउंड, देहरादून

आकर्षण

साहित्यिक चर्चाएँ | बाल गतिविधियाँ | सांस्कृतिक कार्यक्रम | आर्ट गैलरी | फूड कोर्ट

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : nbtexhibition3@gmail.com

nbt.india
एकः सूते सकलम्

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
Ministry of Education, Government of India

5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, वसंत कुंज,
नई दिल्ली–110070
ईमेल : office.nbt@nic.in
वेबसाइट : www.nbtindia.gov.in

हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

नई दिल्ली | पुणे | बेंगलुरु | कोलकाता | चेन्नई | हैदराबाद | गुवाहाटी | अगरतला | पटना | कटक | कोच्चि | भोपाल | देहरादून | लखनऊ

Follow us on @nbt_india | instagram.com/nbtindia | YouTube youtube.com/nbtindia | fb.com/NationalBookTrustIndia